



साईं सृष्टि इमारत का तीसरी बार स्लैब गिरा

पांच मंजिला साईं सृष्टि इमारत का पिछला हिस्सा भरभराकर गिरा



कोई जनहानि नहीं

■ पिछला पूरा हिस्सा गिरा

■ उल्हासनगर-3 स्टेशन रोड की घटना

■ हादसे में जनहानि नहीं

उल्हासनगर. उल्हासनगर कैप-3 निवासी चौक के पास स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर सोमवार रात को उस समय हड़कंप मच गया, जब तीसरी बार धोकादायक पांच मंजिला साईं सृष्टि इमारत का पिछला पूरा हिस्सा और स्लैब गिर गया। इससे पूर्व भी इसी खाली पडोई इमारत का दो बार स्लैब गिर चुका है। पास में स्कूल व दुकानें हैं।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही उल्हासनगर महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

सुरक्षा के मद्देनजर इमारत के आसपास का क्षेत्र खाली कराया गया और दोनों ओर से सड़क को

महापौर की अगुवाई में तोड़ी जा रही इमारत

मंगलवार को इस इमारत को तोड़ने का कार्य महापौर अश्विनी कमलेश निमक की देखरेख में शुरू किया गया। महापौर ने बताया कि भीड़ वाले इलाके में इस इमारत को सुरक्षा के लिहाज से तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। परिसर के दुकानों को बंद रखा गया है और जल्द से जल्द इसे तोड़कर परिसर को सुरक्षित किया जाएगा।

बंद कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय शुरू किए।

उल्हासनगर महानगरपालिका के अग्निशमन अधिकारी एस.पी. बॉम्बे ने बताया कि इमारत के पिछले हिस्से का स्लैब गिरा है।

एहतियात के तौर पर क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

500 वर्गफुट की झुगियों को मालिकाना हक



■ 31 दिसंबर, 2026 तक किया जा सकता है आवेदन - MLA बालाजी किणीकर

उल्हासनगर. महाराष्ट्र सरकार की जमीन पर 2011 से पहले बनी झुगियों में रहनेवालों को उनके घरों का मालिकाना हक मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए MLA बालाजी

किणीकर और सब-डिवीजनल ऑफिसर विजयानंद शर्मा ने मनापा की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को उल्हासनगर सब-डिवीजनल ऑफिस में विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। मीटिंग की अध्यक्षता MLA बालाजी किणीकर ने की। इस अवसर पर राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी सरकारी निर्णय के मुताबिक, 1 जनवरी, 2011 तक



सरकारी जमीन पर हुए रिहायशी कब्जों को रेगुलराइज करने की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को उल्हासनगर सब-डिवीजनल ऑफिस में विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। मीटिंग की अध्यक्षता MLA बालाजी किणीकर ने की। इस अवसर पर राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी सरकारी निर्णय के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से

चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार, शहर सर्वेक्षण अधिकारी, मनापा के सहायक आयुक्त, महावितरण के उप अभियंता और उपविभागीय अधिकारी (सदस्य सचिव) के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। शिवसेना की ओर से शहर प्रमुख सचिन कदम, नगरसेवक प्रदीप गोडसे, सुरज सोनकांबले, सुशील पवार, अनिल

व्यावसायिक अतिक्रमण नियमित नहीं होंगे

- इस बैठक में उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2011 को या उससे पहले सरकारी जमीन पर हुए केवल रिहायशी अतिक्रमण ही नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
- आरक्षित भूमि, सार्वजनिक उपयोग की जमीन, सड़क, नाले, नदी, जंगल की जमीन, रेलवे और राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
- इसी तरह, दुकान, गोदाम, होटल समेत सभी तरह के व्यावसायिक अतिक्रमण नियमित नहीं किए जाएंगे।
- सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 500 वर्ग फीट तक के रिहायशी अतिक्रमणों का नियमितीकरण मुफ्त में किया जाएगा।
- वहीं, 500 से 1500 स्क्वेयर फीट के परिसरों के लिए तय कीमत का 10 परसेंट फीस ली जाएगी। 1500 स्क्वेयर फीट से ज्यादा के कब्जे को रेगुलर नहीं किया जाएगा।
- कब्जे के सबूत के तौर पर वोटर लिस्ट, बिजली का बिल, टैक्स की रसीद, सरकारी डॉक्यूमेंट या दूसरे मंजूर रिकॉर्ड जमा करने होंगे। एक परिवार इस स्कैम का फायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकता है।

मराठे, ज्ञानेश्वर करवंदे और अन्य

गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

उल्हासनगर में 105 वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई

■ 1.12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया

■ कल्याण-बदलापुर रोड पर गैर-कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई

■ व्यापारी नाराज

■ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी

उल्हासनगर. उल्हासनगर ट्रैफिक सब-डिवीजन ने सोमवार को कल्याण-बदलापुर रोड पर गैर-कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान में 105 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 1 हजार 12 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह खास अभियान पुलिस निरीक्षक युवराज सरनोबत के मार्गदर्शन में चलाया गया। इसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोरख चौधरी, असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर पंढरीनाथ काले, पुलिस कांस्टेबल नाना आव्हाड,



गोरक्षनाथ दराडे, विशाल गोरले और प्रशांत परदेशी की टीम ने हिस्सा लिया। यह कार्रवाई कल्याण-बदलापुर रोड पर शांतिनगर से डब्लू चौक तक के

इलाके का बाजार में पुरानी गाड़ी बेचने वालों, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गैरज ड्राइवों और कार डेकोरेटर्स के खिलाफ की गई, जो अपनी दुकानों के सामने अपनी

गाड़ियां पार्क कर रहे थे। यह देखा गया कि पब्लिक सड़कों पर रिपेयर के लिए खड़ी गाड़ियां और दुकानों के बाहर डेकोरेशन के लिए खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट डाल रही थीं। चूंकि कल्याण-बदलापुर रोड बहुत बिजी रोड है, इसलिए इस तरह की गैर-कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक में बड़ी रुकावट आ रही है। इसलिए, भविष्य में ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस निरीक्षक युवराज सरनोबत ने चेतावनी दी।

भाजपा नेता किरीट सोमय्या उल्हासनगर में

■ SIAR बाबत भाजपा मुख्यालय में ली बैठक

उल्हासनगर. उल्हासनगर भाजपा जिला मुख्यालय में SIAR विषय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व सांसद किरीट सोमय्या विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनका स्वागत उल्हासनगर जिलाध्यक्ष राजेश वर्धन्या ने किया। उन्होंने आए हुए सभी भाजपा पदाधिकारियों



व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बैठक में SIAR से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा

की गई तथा संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

श्री सोमय्या ने कहा कि सभी कार्यकर्ता नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य करें तथा संगठनात्मक रूप से पूरी तत्परता के साथ कार्य करें। बैठक में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जनजागरण अभियान को प्रभावी बनाने का संकल्प लिया।

बुवापाड़ा की जमीन पर अवैध घर को वैध की योजना लागू नहीं होती -महंत तेजनारायणदास

■ ये जमीन हमारी मिल्कियत है

अंबरनाथ. अंबरनाथ (प.) के बुवापाड़ा परिसर में ये अफवाह किसी ने फैला दी है कि बुवापाड़ा की भूमि पर बसे अतिक्रमण धारक घरों अथवा किरायादारों की भी महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित किए गए योजना के अनुसार घरों को अनावैध साबित करके प्राप्ती कांड मिलेगा. इस अफवाह का खंडन महंत तेजनारायण दास गुरु महंत शामलदास ने करते हुए अंबरनाथ



सरकारी जमीन का अतिक्रमण नियमित करने बाबत शासन का निर्णय हुआ है. शासन निर्णय की

शर्तें हमारी जमीन पर बसे किरायेदार-अतिक्रमणधारकों पर लागू होती नहीं है. बाबा महंत तेजनारायण दास ने आगे लिखा है कि हमें ये सुनने और देखने को मिल रहा है कि कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे बुवापाड़ा की जमीन पर बसे हुए किरायेदार एवं अतिक्रमण धारकों में अफवाह फैलाकर दिशाभूल कर रहे हैं और उनको बेकायदा इस योजना का

लाभ लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं. बाबा ने मुख्याधिकारी से कहा है कि हमारे बुवापाड़ा की भूमि पर कोई योजना पर अमल ना किया जाए. अगर ऐसा हुआ तो हमारा भारी नुकसान होगा. अगर ऐसा हुआ तो हमारे नुकसान भरपाई की पूरी जिम्मेदारी आपकी व आपके कार्यालय की होगी. इस विषय के संदर्भ में हमारे वकील मार्फत कानूनी हरकत व कार्रवाई बाबत ये हक अधिकार अबाधित रखकर फिलहाल हरकत अर्ज पेश किया गया है.

उल्हासनगर के नगरसेवक पहुंचे गुवाहाटी

■ मनपा की तिजोरी खाली और स्टडी टूर पर 65 लाख खर्च

■ 22 से 26 जुलाई के बीच हुआ था टूर

■ टूर पर उठ रहे सवाल



उल्हासनगर मनपा सचिव के ऑफिस के मुताबिक, यह स्टडी टूर 22 से 26 जुलाई के बीच हुआ था। ट्रेनिंग गुवाहाटी के फाइव-स्टार रेडिसन ब्लू होटल में प्रोजेक्ट थी। इस चार दिन के ट्रे के दौरान, हर कॉर्पोरेटर पर 52,980 रुपये खर्च करने का प्लान था, जिसमें चार टी ब्रेक, पांच लंच, चार डिनर, और पांच दिनों तक शहर के अंदर प्रोजेक्ट विजिट के लिए कार, होल, ट्रेवल खर्च और स्टेशनरी का इंतजाम शामिल था। मुंबई-

गुवाहाटी-मुंबई यात्रा के लिए 21,740 रुपये देने थे। इसलिए, हर व्यक्ति पर 74,720 रुपये खर्च होने का अनुमान था। इस टूर के लिए कुल 65 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई, ऐसा मनपा सचिव के ऑफिस ने बताया।

■ संस्था मुंबई की, ट्रेनिंग गुवाहाटी में

यह ट्रेनिंग मुंबई में ऑल इंडिया लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन ने दी, ऐसा मनपा की

दूर या मॉनसून टूरिज्म?

यह ट्रेनिंग टूर 76 कॉर्पोरेट्स के लिए ऑर्गनाइज किया गया था, लेकिन पता चला है कि उनमें से कुछ ने जाने से मना कर दिया। वहीं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो से पता चला कि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स फेमिली टूर पर गए थे। इसलिए, कई लोगों को हैरानी हुई कि यह स्टडी टूर था या मॉनसून टूरिज्म। यह भी सवाल उठ रहा है कि कॉर्पोरेट्स के अलावा फेमिली मेंबर्स का खर्च किसकी जेब से जाएगा।

पीआर ऑफिसर प्राजक्ता कुलकर्णी ने बताया। असेंबली साईंस और फंक्शनिंग, मुद्दे, सवाल बनाना, फाइल बनाना, वाई डेवलपमेंट और प्लानिंग जैसे सबजेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी गई। लेकिन, गुवाहाटी में मुंबई के किसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत थी? यह भी सुझाव दिया गया है कि यही ट्रेनिंग मनपा मुख्यालय में ही ऑर्गनाइज की जा सकती थी।

उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल हालत नाजुक है। म्युनिसिपैलिटी को MIDC से कॉन्ट्रैक्टर के बिल और पानी के बिल भरने में मुश्किल हो रही है। म्युनिसिपैलिटी पर लगभग 700 करोड़ का बकाया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में लगातार नाकामी गड़लों रही है। शहर में सड़कों और मृत्तों का मुद्दा अभी भी पेंडिंग है। दो महाने बाद भी म्युनिसिपल स्कूलों के स्टूडेंट्स को स्कूल मटेरियल नहीं दिया गया है।

जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं. - वाल्मीकि

विकास

संपादकीय

सुरक्षा नियमों की अनदेखी

यह विचित्र बात है कि एक तरफ भारत अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, मशीनीकरण और कृत्रिम मेधा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, दूसरी ओर गंदे नालों और सीवेज टैंक की सफाई आज भी बिना सुरक्षा उपकरणों के हाथ से कराई जा रही है, जो कई बार मौत का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-150 में बीते शनिवार की रात को हुई, जब सीवेज टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक श्रमिक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई।

आखिर क्या कारण है कि तमाम दिशा-निर्देशों और नियम-कानून के बावजूद उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि सफाई कार्य से जुड़े लोग समाज के निचले और कमजोर तबके के होते हैं, जिनकी शासन-प्रशासन तक सीधी पहुंच नहीं होती है! अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के जोखिम भरे कार्य में कैसे झोंक दिया जाता है?

सरकारी की ओर से बीते मार्च में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से देश में सीवर और सीवेज टैंक की सफाई के दौरान करीब 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 539 परिवारों की ही पूरा मुआवजा मिल पाया। ये वे आंकड़े हैं, जिन घटनाओं की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, मगर इससे कहीं अधिक मामले ऐसे होते हैं, जो कहीं दर्ज हो नहीं हो पाते हैं। ऐसे में न तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और न ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल पाती है।

देश में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को सीवर या सीवेज टैंक में बिना सुरक्षा मानकों के उतारना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में एक अहम फैसले में कहा था कि इस तरह के कार्य के दौरान होने वाली हर मौत के लिए सरकार जवाबदेह है। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह सीधे तौर पर शासन-प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है।

क्या आप जानते हैं भारत की सबसे छोटी नदी का नाम?

क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी नदी भी है, जिसकी लंबाई महज 45 किलोमीटर है? आकार में छोटी

जरा हट के

होने के बावजूद यह नदी अपने इतिहास, पर्यावरण और पुनर्जीवन की प्रेरणादायक कहानी के कारण बेहद खास मानी जाती है।

राजस्थान के अलवर जिले में बहने वाली अरवरी नदी को भारत की सबसे छोटी नदियों में

गिना जाता है, यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अगे चलकर सरसा नदी में मिल जाती है। अरवरी कोई बारहमासी नदी नहीं है, बल्कि यह वर्षा पर निर्भर करती है, मानसून के दौरान इसमें पानी भर जाता है और आसपास का इलाका हरियाली से खिल उठता है, जबकि गर्मियों में इसका बहाव काफी कम हो जाता है, हालांकि लंबाई के लिहाज से यह नदी छोटी है, लेकिन आसपास के गांवों के लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है।



अरवरी नदी खेतों की सिंचाई, भूजल स्तर को बनाए रखने और स्थानीय लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि इसे इस क्षेत्र की जीवनरेखा भी कहा जाता है। अरवरी नदी की सबसे

खास बात इसका पुनर्जीवन है। करीब तीन दशक पहले यह नदी लगभग सूख चुकी थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली 'जोहड़' का सहारा लिया और कई छोटे-छोटे मिट्टी के बांध बनाए, इन संरचनाओं ने वर्षा जल को रोकने और भूजल को फिर से रिचार्ज करने में बड़ी भूमिका निभाई। धीरे-धीरे इसका असर दिखाई देने लगा और वर्षों से सूखी पड़ी अरवरी नदी में

फिर से पानी बहने लगा। अगर आप राजस्थान की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अरवरी नदी के आसपास का इलाका भी आपकी सूची में शामिल हो सकता है, यहां आपको ग्रामीण जीवन की सादगी, अरावली की शांत पहाड़ियां और प्रकृति के बीच सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा, इसके साथ ही सरसका टाइगर रिजर्व, भानुगढ़ किला, सिलीसेढ़ डील और अलवर सिटी पैलेस जैसी प्रसिद्ध जगहें भी पास में मौजूद हैं।

विमर्श

विकसित भारत के लक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सीढ़ी शिक्षा है, लेकिन हाल के आंकड़े इस सीढ़ी की कमजोरी दर्शाते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 56 प्रतिशत स्नातक ही आज किसी छोटे-मोटे रोजगार के योग्य माने जा सकते हैं। औसतन हर दो में से एक युवा डिग्री लेकर भी समकालीन रोजगार बाजार की जरूरतों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। दूसरी ओर इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स के अनुसार एआई और मशीन लॉनिंग से जुड़ी भूमिकाओं में रोजगार के अवसर पिछले एक साल में 46 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि एचआर, डिजिटल मार्केटिंग और सामान्य प्रशासन जैसी पारंपरिक नौकरियों की मांग लगातार घट रही है।

अमेरिका, चीन, जापान सहित

यूरोप के विश्वविद्यालय इस बदलाव को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि उन्होंने एआई के कारण अपने पारंपरिक कार्यक्रमों की घटती मांग को देखते हुए न सिर्फ उनकी फीस कम कर दी है, बल्कि बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप अपने विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन भी किया है। चीन ने पिछले महीने अपने 12 हजार से अधिक (लगभग एक तिहाई) स्नातक डिग्री कार्यक्रमों को अप्रासंगिक मानते हुए बंद कर दिया। ये वे पाठ्यक्रम थे, जो समकालीन और भविष्य के जवाब मार्केट से मेल नहीं खाते। उनकी जगह चीन ने एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम एप्लीकेशन और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसकी मूल वजह यह थी कि वहां एक ओर



डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही थी और प्रतिष्ठानों की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कर्मी नहीं मिल पा रहे थे।

भारत में भी पुराने और परंपरागत कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को तत्काल समाप्त या संशोधित करने की आवश्यकता है। उभरते हुए रोजगार परिदृश्य और कोशल आवश्यकताओं को अनुरूप अपने शिक्षा-तंत्र को बदलकर ही हम उसे प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं। आज फैक्ट्री

से लेकर बाजार तक और डिजाइनिंग स्टूडियो से लेकर फाइनेंसियल एनालिसिस तक एआई साथ-साथ काम कर रही है। इस नए युग को 'स्किल आगमेशन' की जरूरत है, जहां तकनीक इसान की जगह नहीं लेती, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाती है।

इसी कारण पिछले केंद्रीय बजट में 'शिक्षा के लिए एआई' उल्लेखित करने हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसे इंडिया एआई मिशन के साथ जोड़ा गया है। हमें इस मद में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। साथ ही एआई को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पुनर्व्याख्यायित

और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। शिक्षा और शोध में अधिकतम निवेश करने वाले देश ही आर्थिक महाशक्ति बनते हैं। पाठ्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने के क्रम में हमें मानविकी को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार बदलना है। इतिहास को डाटा विजुअलाइजेशन के साथ, साहित्य को कंटेंट स्ट्रेटेजी और डिजिटल नैटिव के साथ दर्शन को एआई एथिक्स के साथ और भाषाविज्ञान को कंयूटेशनल सिमेंटिक्स के साथ जोड़ना होगा। इसे ही डिजिटल ह्यूमैनिटीज और कल्चरल एनालिटिक्स कहा जाता है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम को भी लीगेसी तकनीकों से निकालकर सिस्टम थिंकिंग और एनर्जी ट्रांजिशन के इर्द-गिर्द बनाना होगा।

हमें लचीलेपन और बहु-विषयकता को बढ़ावा देना चाहिए। एक छात्र बीकाम के साथ डाटा एनालिटिक्स पढ़ सके, बीए के साथ कोडिंग सीख सके, विज्ञान के साथ उद्यमिता का प्रोजेक्ट कर सके। एनईडी का मेजर-माइनर सिस्टम इसी सोच से आया है। दीवारें तोड़कर वालायन बनाने होंगे। कला, वाणिज्य, विज्ञान के पुराने खांचे अब काम नहीं आएंगे। समाज, उद्योग और बाजार के साथ सहवर्ती संबंध और निरंतर संवाद होना चाहिए। पाठ्यक्रम बंद कर्मों में नहीं बनने चाहिए। टीसीएस, इन्फोसिस, एमएसएमई, स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्षेत्रीय उद्योगों को बोर्ड आफ स्टडीज में जगह मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल दो माह की औपचारिकता न होकर छह माह की परियोजना होनी चाहिए।

छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल

एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की वजह से असंतोष पैदा हो, तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अगर सरकार की उदासीनता की वजह से लोग अपनी बात कहने सड़क पर उतरे, तो उन्हें रोकने के लिए बातचीत की गुंजाइश निकालने के बजाय दमन का रास्ता अख्तियार किया जाए। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लोक के मुद्दे पर जब विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की, तो सरकार के पास वक्त था कि वह संवाद के जरिए एक आदर्श समाधान सामने रखे।

अगर इस दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका होती, तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी हर वह विकल्प आजमाए जाने चाहिए थे, जिससे प्रदर्शन बेलागम न हो और न ही पुलिस को हिंसक बलप्रयोग करने की जरूरत पड़े। मगर अपनी मांगों के साथ 'संसद मार्च' का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, उससे यह सवाल उठा है कि सरकार देश के लोकतांत्रिक



दांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है। गौरतलब है कि नीट प्रश्नपत्र लोक होने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने ऑफ गेस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। मगर इस क्रम में ज्यादा गंभीर आरोप यह सामने आया कि आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से पेलेट गन भी चलाया गया। वहीं पुलिस के इस रवैये के विरोध में जब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हुए, तो वहां भी गैरजल्दारी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया।

एक अन्य आरोप के मुताबिक, बिहार के सिवान में एक पुलिसकर्मी ने एके-47 राइफल से विद्यार्थियों पर गोशियां चलाई। सवाल है कि महज प्रश्नपत्र लोक होने के मसले पर अपना विरोध जताने वालों के खिलाफ घातक हथियार चलाने की हद तक जाकर पुलिस ने आखिर क्या संदेश देना चाहती है। क्या ऐसे आरोपों के बाद अनिवार्यता की

दलील पर विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है? यों आज के दौर में अमूमन हर सार्वजनिक गतिविधि की जीवंत तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप भी लगे, तो क्या यह संविधान और देश के लोकतांत्रिक दांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान नहीं है? कायदे से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को लेकर सरकार को खुद सजग रहना चाहिए था।

मगर विचित्र है कि यह सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण और कानूनसम्मत प्रदर्शन का अधिकार संविधान के हाथों संरक्षित है और केवल आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन खत्म होने के बाद कई जगहों से ऐसी खबरें आंईं कि हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा कर कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह आंदोलनकारियों से किए गए वादे से सरकार के मुकदमे की तरह है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बेवजह नहीं है कि विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका मिला है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है।



सामग्री

- कॉर्नफ्लोर: आधा कप
- चीनी: डेढ़ कप
- पानी: 2 कप
- देसी घी: एक चौथाई कप
- नींबू का रस: 1 छोटी चम्मच
- फूड कलर: 2 चुटकी
- कटे हुए मेवे: 2-3 बड़े चम्मच
- इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच

विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में आधा कप कॉर्नफ्लोर लें और उसमें 1 कप पानी डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। अब गैस पर एक भारी लेप वाली कड़ाही रखें। इसमें डेढ़ कप चीनी और बचा हुआ

बॉम्बे-कराची हलवा



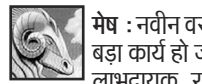
बिल्कुल धीमा कर दें। कॉर्नफ्लोर वाले घोल को एक बार चम्मच से चलाएं और फिर धीरे-धीरे कड़ाही में डालते जाएं। दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न पड़े।

कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि मिश्रण गाढ़ा और जेली की तरह पारदर्शी होने लगा है। इस समय इसे लगातार चलाता बहुत जरूरी है, वरना यह तले में चिपक कर जल सकता है।

जब हलवा गाढ़ा होने लगे, तो इसमें एक-एक चम्मच करके देसी घी डालना शुरू करें। एक चम्मच घी डालें, उसे हलवे में पूरी तरह मक्स होने दें और फिर दूसरा चम्मच डालें। जब हलवा सारा घी सोख ले, तब इसमें थोड़े से पानी में घोलकर अपना मनपसंद फूड कलर डाल दें। साथ ही, इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें। जब मिश्रण कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो गैस बंद कर दें। एक थाली या ट्रे में पहले से थोड़ा-सा घी लगाकर उसे चिकना कर लें। अब इस गरमागरम मिश्रण को ट्रे में निकालकर बराबर फैला दें। ऊपर से थोड़े-थोड़े ड्राई फ्रूट्स सजा दें। इसे 2 से 3 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर सेट होने के लिए छोड़ दें। जब यह अच्छे से सेट हो जाए, तो चाकू से अपने मनचाहे आकार के चौकोर टुकड़ों में काट लें।



आज का राशिफल



मेष : नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य हो जाने से प्रसन्नता रहेगी। निवेश लाभदायक रहेगा। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। विवाद से बचे। आवश्यक वस्तु मुम हो सकती है।

वृषभ : व्यापार में वृद्धि होगी। आय होगी। विवेक का प्रयोग करें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवृद्धि से तनाव रहेगा। किसी व्यक्ति के उद्वेगों में न आए। विवाद से बचे। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

मिथुन : नए अनुबंध हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बकया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लंबी यात्रा हो सकती है। लाभ होगा। प्रशंसा मिलेगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। प्रमाद न करें।

कर्क : व्यवसाय मनीमुकूल लाभ देगा। कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोखिम न लें। भाइयों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे।

सिंह : राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण व लाभदायक रहेगी। कारोबार मनीमुकूल रहेगा। शेयर मार्केट में जोखिम न लें। नौकरजी में वेन रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। दूतजन हानि पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें। तीर्थदर्शन हो सकता है। सत्संग का लाभ मिलेगा।

कन्या : व्यापार ठीक चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य बिल्कुल न करें। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग से हानि की आशंका है, सावधानी रखें। दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करें। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्षोभ होगा। फालतू की बातों पर ध्यान न दें।



तुला : राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। कारोबार से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। कोई बड़ा कार्य करने की योजना बन सकती है। कार्यसिद्धि होगी। सुख के साधनों पर व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। शत्रुओं का पराभव होगा।

वृश्चिक : प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार में वृद्धि के योग है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यस्तता रहेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं।

धनु : बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रवृद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। पारिवारिक मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मेहनत का फल पूरा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर : नए मित्र बनेंगे। अच्छी खबर मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। कार्यों में गति आएगी। विवेक का प्रयोग करें। लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। व्यापार ठीक चलेगा। घर-बाहर सुख-शांति रहेगी। पुराने सगी-साथी व रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

मीन : नए मित्र बनेंगे। अच्छी खबर मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। कार्यों में गति आएगी। विवेक का प्रयोग करें। लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। व्यापार ठीक चलेगा। घर-बाहर सुख-शांति रहेगी। पुराने सगी-साथी व रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

असली और नकली खजूर में क्या होता है अंतर?

खजूर प्राकृतिक रूप से फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। यही वजह है कि इसे ऊर्जा देने वाला सुपरफूड भी कहा जाता है। लेकिन कई बार खजूर को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए उस पर कृत्रिम रंग, ग्लिसरीन या वैक्स जैसी परत चढ़ा दी जाती है, ऐसे उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित दिखते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ सकते हैं। अगर खरीदारी के दौरान थोड़ी सतर्कता बरती जाए तो असली और नकली खजूर में फर्क करना मुश्किल नहीं है।

रंग और चमक से करें पहली पहचान बहुत ज्यादा चमकदार खजूर से रहें **सावधान**: असली खजूर का रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे तक हो सकता है, इसकी सतह सामान्य तौर पर मैट यानी बिना ज्यादा चमक वाली होती है, वहीं नकली या कृत्रिम रूप से कोटिंग किए गए खजूर असामान्य रूप से चमकदार, चिकने और कई बार चिपचिपे महसूस होते हैं। अगर किसी दुकान पर सधी खजूर एक जैसे चमकदार दिख रहे हों, तो उन्हें खरीदने से पहले ध्यान से जांच लेना बेहतर होगा।

बनावट और स्वाद भी बताते हैं सच्चाई प्राकृतिक मिठास ही होती है असली **पहचान**: असली खजूर हल्के नरम होते हैं और चबाने पर उनकी प्राकृतिक मिठास धीरे-धीरे महसूस होती है। दूसरी ओर, नकली या



अधिक प्रोसेस किए गए खजूर कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त होते हैं या उनमें मिठास कृत्रिम लगती है। घर में बच्चों या बुजुर्गों के लिए खजूर खरीदते समय इसकी बनावट पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि प्राकृतिक खजूर आसानी से चबाए जा सकते हैं। खजूर से भी पहचान सकते हैं असली खजूर असली खजूर में हल्की और प्राकृतिक मीठी खुशबू होती है, यदि खजूर से तेज कैंकिमल जैसी गंध या अजीब महक आए तो यह संकेत हो सकता है कि उस पर किसी प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया की गई है। विशेषज्ञ

भी सलाह देते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गंध पर ध्यान देना एक अच्छी आदत है।

पानी वाला आसान टेस्ट घर पर करें कुछ मिनटों में मिल सकता है **जवाब**: अगर आपको किसी खजूर की गुणवत्ता पर संदेह है, तो घर पर एक आसान टेस्ट किया जा सकता है, कुछ खजूर सफा पानी में डाल दें, यदि उन पर लगी कृत्रिम रंग या कोटिंग पानी में उतरने लगे या पानी का रंग बदलने लगे, तो ऐसे खजूर से बचना बेहतर है, हालांकि यह तरीका हर स्थिति में अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन शुरुआती जांच के लिए उपयोगी हो सकता है।

असली खजूर खाने के फायदे प्राकृतिक खजूर शरीर को जल्दी ऊर्जा देने में मदद करते हैं, इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होता है, साथ ही आयरन, पोटेशियम और अन्य मिनरल्स शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं, संतुलित मात्रा में खजूर खाना हेलदी डाइट का हिस्सा बन सकता है।

बरसात में घर की छत टपकने लगी है?



■ एक्सपर्ट के ये उपाय दूर करेंगे सीलन और लीकेज की समस्या

बरसात के मौसम में अक्सर घरों में सीलन और पानी के लीकेज (रिसाव) की समस्या देखने को मिलती है, इससे न सिर्फ घर की दीवारों और छत खराब होती हैं, बल्कि लोग भी काफी परेशान रहते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के दौरान ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझते हैं।

■ शुरुआती लापरवाही बनती है बड़ी वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि सीलन और लीकेज की सबसे बड़ी वजह मकान बनते समय की गई लापरवाही होती है, जब मकान का ढांचा (स्ट्रक्चर) खड़ा होता है और नींव सही जाती है, उस समय विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी होता

है, यदि नींव तय करने या स्ट्रक्चर में थोड़ी सी भी ऊंच-नीच या गड़बड़ी रह जाती है, तो आगे चलकर मकान की दीवारों और छतों में क्रैक (दरारें) आ जाते हैं।

■ कैसे करें इस समस्या का समाधान

अगर आपके घर में भी सीलन या दरारें आ गई हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए आसान और प्रभावी उपाय बताए हैं:

1. छोटी-मोटी दरारों और सीलन के लिए

अगर छत या दीवारों पर हल्की-फुल्की दरारें हैं जिन्हें सीलन आ रही है, तो बाजार में कई तरह के डैम्प प्रूफ उत्पाद उपलब्ध हैं, इनका 1-2 कोट लगाने से ही लीकेज और सीलन की समस्या से तुरंत राहत मिल जाती है।

2. बड़ी और गहरी दरारों के लिए क्या करें

यदि मकान में ज्यादा या बड़ी दरारें आ गई हैं, तो इन्हें सिर्फ डैम्प प्रूफ से ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए सीमेंट और बजरी (मसाले) के साथ सही अनुपात में डैम्प प्रूफ केमिकल मिलाकर दरारों को भरना होता है।

लेख में दी गई समस्त जानकारियाँ और सूचनाएँ सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. 'उत्थास विकास' इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमत करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.

संक्षेप...

3 साल से फरार
हथियार सप्लायर
गिरफ्तार

मुंबई. मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच (यूनिट 6) ने 'महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) के तहत दर्ज हत्या और अवैध हथियार आपूर्ति के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी सुमित स्वस्तिक सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अवैध आग्नेयास्त्र (हथियार) सप्लाई करने का काम करता था और पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इस समय नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे सेक्टर 19, गीतांजलि ज्वेलर्स के पास, खारघर (नवी मुंबई) से हिरासत में ले लिया।

शरद पवार बोले- एनसीपी के
दोनों गुट साथ नहीं आएंगे■ एक दिन पहले बेटी
सुप्रिया अमित शाह
से मिली थी

मुंबई. शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के फिर से साथ आने का कोई सुवाल ही नहीं है। एक दिन पहले NCP (शरद गुट) की सांसद सुप्रिया सुले को सांसद बजरंग सोनवणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यह मुलाकात सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन का निमंत्रण देने के लिए हुई थी। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि शरद पवार गुट भाजपा के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो सकता है।

■ गिरीश महाजन बोले-
अभी कुछ नहीं कहा जा
सकता

एनसीपी (शरद पवार) प्रमुख शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि शरद पवार और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात में क्या बातचीत हुई, यह कोई नहीं जानता। फिलहाल सिर्फ

अफवाहें और अटकलें हैं। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

■ 22 जुलाई को शरद
पवार पीएम से मिले थे

इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रिया सुले और शरद पवार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। शरद पवार ने मोदी को एक पत्र भी सौंपा था। यह बैठक करीब 20 मिनट चली थी।

बैठक को लेकर शरद पवार ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में कहा- NEEET परीक्षा के पेपर लीक, इसके खिलाफ छात्रों के आंदोलन, आंदोलन के दौरान पुलिस के गलत व्यवहार और छात्रों पर दर्ज आपराधिक मामलों समेत कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से चर्चा हुई।

मिनी लोक अदालत में 149 एक्सीडेंट क्लेम निपटाए

■ पीड़ितों को 17.80
करोड़ रुपये का
मुआवजा

ठाणे. जिले में पहली बार आयोजित 'मिनी लोक अदालत' में 149 मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के क्लेम निपटाए गए। इन क्लेम के सफल निपटारे के बाद, एक्सीडेंट पीड़ितों और मृतकों के वारिसों को 17 करोड़ 80 लाख 96 हजार रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया। एक मामले में, मृतक के वारिसों को रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। ठाणे डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में आयोजित इस खास लोक अदालत के कारण मेंडिंग क्लेम का तेजी से निपटारा हुआ और पीड़ितों को राहत मिली।

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई के गाइडेंस में, ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला और



सेशंस जज आर. डी. सावंत ने 'मिनी लोक अदालत' आयोजित की। ठाणे डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केस निपटाए गए। इस मौके पर दो अलग-अलग पैनल बनाए गए थे।

149 मोटर एक्सीडेंट कम्पेनसेशन क्लेम के सफल सेटलमेंट के बाद वारिसों को कुल 17.80 करोड़ 96 हजार रुपये का कम्पेनसेशन मंजूर किया गया। पिछली नेशनल लोक अदालत 9

मई, 2026 को हुई थी, जबकि अमली नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर, 2026 को होगी। ठाणे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी रवींद्र एस. पंजकर ने कहा कि इन दो लोक अदालतों के बीच चार महीने के गैप को देखते हुए, यह पहल इसलिए शुरू की गई ताकि यह पक्का हो सक कि एक्सीडेंट के शिकार लोगों को कम्पेनसेशन पाने के लिए और ईंतज़ार न करना पड़े।

मोटर एक्सीडेंट के
वारिसों को 1 करोड़
80 लाख रुपये का
मुआवजा

इस लोक अदालत में सबसे खास मोटर एक्सीडेंट केस में विजय कुमार (उम्र 36) के वारिसों को 1 करोड़ 80 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया। विजय कुमार, जो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, मुंबई-गोवा हाईवे पर अंबेवाड़ी नाका (ता. रोहा, जिला रायगढ़) पर एक तेज रफतार ट्रेलर से टक्कर में मारे गए थे। जज आर. डी. मोहिते की कोर्ट में केस का निपटारा डिस्ट्रिक्ट जज डी. बी. माने की गाइडेंस में हुआ। इसके बाद, ऑरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 1 करोड़ 80 लाख रुपये का चेक दिया गया।



ठाणे. विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम एकनाथ संभाजी शिंदे और लता एकनाथ शिंदे का एन्क्यूअरेशन फॉर्म भरा गया। इस मौके पर सर्जेंस राय मरुकेपाटिल, उपजिलाधिकारी और वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 147 कोपरी पंचाखड़ी विधानसभा क्षेत्र, पुणेधाम थोरात, तहसीलदार और छठे वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 147 कोपरी पंचाखड़ी विधानसभा क्षेत्र, राजेश सोनवणे, सहायक आयुक्त मनपा संजय साळुंके, नायब तहसीलदार रूपाली दाते, B.L.O., बापू पारेकर, रेवेन्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर वैभव पडवल, वर्ल्ड हारुन शेख मौजूद थे।

टोरेट पावर ने अति जर्जर 266 इमारतों को जारी किए नोटिस

■ बिजली सुरक्षा को दी
प्राथमिकता

भिवंडी. मानसून के दौरान विद्युत दुर्घटनाओं की बढ़ती संभावना को देखते हुए टोरेट पावर ने फ्रेंचाइजी क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा एवं उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया है। पहल का उद्देश्य सुरक्षित बिजली उपयोग को बढ़ावा देना तथा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। अभियान के अंतर्गत विद्युत दुर्घट से असुरक्षित पाई गई 266 इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं।

■ वर्गीकृत करके दिया
नोटिस

मनपा से मिली सूची के आधार पर जर्जर इमारतों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में जहां मीटर के बिना अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है, टोरेट पावर द्वारा अनधिकृत कनेक्शनों को हटाने हेतु नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जाते रहे हैं बावजूद कुछ लोग अपने स्वयंश्रु अनधिकृत बिजली उपयोग जारी रखते हैं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। मानसून के दौरान



ऐसे नेटवर्क और भी अधिक खतरनाक साबित होते हैं। इमारतों को नोटिस देकर बावजूद अंदर की वायरिंग और मीटर से उपभोक्ता के परिसर तक जाने वाली वायरिंग

टोरेट पावर की ग्राहकों से अपील

टोरेट पावर जन संपर्क अधिकारी चेतन बदियानी ने सभी उपभोक्ताओं, हाउसिंग सोसायटियों, मकान मालिकों एवं संपत्ति धारकों से अपील करती है कि, जीवन सुरक्षा की खातिर अधिकृत बिजली कनेक्शन का उपयोग करें। अपनी विद्युत व्यवस्था की नियमित जांच एवं रखरखाव सुनिश्चित करें, ताकि विद्युत दुर्घटनाओं को रोक जा सके। सुरक्षित वायरिंग, अधिकृत बिजली कनेक्शन, सुरक्षित जीवनर को प्राथमिकता देकर अपनी सुरक्षा के

सुरक्षित है। रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है, य इमारतों को नोटिस देकर लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जरूरी मरम्मत और नवीनीकरण का काम

सुभाषनगर-गांधीनगर SRA प्रोजेक्ट को रफ्तार

विधायक संजय
केलकर की SRA
ऑफिस में मीटिंग

ठाणे. सुभाषनगर गांधीनगर में कई सालों से रुके हुए एसआरए प्रोजेक्ट में अन्याय झेल रहे निवासियों को न्याय दिलाने के लिए विधायक संजय केलकर ने एसआरए ऑफिस में अधिकारियों, निवासियों और डेवलपर के प्रतिनिधियों की जाईंट मीटिंग की। इस मीटिंग में सैकड़ों निवासियों के हित में फैसले लिए गए। अब इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने से निवासियों को राहत मिली है। इस मौके पर नगरसेवक अमित सरैया, नगरसेवक विकास पाटिल, नगरसेवक और ठाणे हाउसिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट सीताराम गणे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, एसआरए ऑफिसर राजकुमार पवार मौजूद



थे सुभाषनगर-गांधीनगर में एसआरए प्रोजेक्ट कई सालों से रुका हुआ है और 1500 से ज्यादा परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। डेवलपर ने निवासियों के घर खाली तो कर दिए, लेकिन कई लोगों को आठ साल से किराया नहीं दिया गया है। इसके अलावा, एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट में फ्रॉड के आरोप भी लगे हैं। यहां के रहने वाले मिस्टर केलकर के पास पहुंचे और अपनी शिकायतें बताईं, जिस पर उन्होंने फॉलोअप शुरू किया। इसी बैकग्राउंड में, मिस्टर केलकर ने सोमवार को

एसआरए ऑफिस में एक जाईंट मीटिंग की। इस मौके पर, उन्होंने रहने वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए डेवलपर और एसआरए एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मीटिंग में पॉजिटिव चर्चा के बाद, रहने वालों के हित में फैसले लिए गए। इसके मुताबिक, जिन रहने वालों का किराया बकाया है, उनकी फाइनल लिस्ट तीन महीने के अंदर तैयार की जाएगी और किराया दिया जाएगा। पहली बिल्डिंग का काम एक हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा और बाकी तीन बिल्डिंग का काम

एक महीने बाद बिना रुके शुरू हो जाएगा। यह भी तय किया गया कि अगर डेवलपर इस मामले में फेल होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए, केलकर ने कहा कि शहर में कई एसआरए प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जहां कुछ प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, वहीं कई जगहों पर डेवलपर्स रहने वालों को गुमराह कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। इन डेवलपर्स के खिलाफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमपीआईडी एक्ट के तहत केस भी फाइल किया गया है। मीटिंग में उन डेवलपर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई जो लोगों पर जुल्म करते हैं और झूठे केस करते हैं। विधायक केलकर ने यह भी साफ किया कि महोरा या एसआरए ऑफिस को डेवलपर्स के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों पर फोकस करना चाहिए।

डिलीवरी बाँय
नाले में गिरा

उल्हासनगर. उल्हासनगर के कैप 4 इलाके में एक घटना हुई जिसमें एक गोमैटो डिलीवरी बाँय नाले में गिर गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डिलीवरी बाँय जब सूरली निवास के पीछे वाली गली से गुजर रहा था, तो उसका पैर नाले के कवर पर पड़ा। उसी समय कवर फिसल गया और वह सीधे नाले में गिर गया। किस्मत से, इस घटना में उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। नाले से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले नाले का कवर ठीक से लगाया, जिससे आगे होने वाले हादसे टल गए। इस बीच, इस घटना ने एक बार फिर उल्हासनगर में नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़

3.04 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन ज़ब्त, तस्कर गिरफ्तार

ठाणे. ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की कंपोनेंट-1 टीम ने 3 करोड़ 4 लाख रुपये की कीमत का 1 kg 520 ग्राम मेफेड्रोन (M.D.) ज़ब्त किया है। इस मामले में सलमान मुन्ना शेख (उम्र 30, निवासी मुंबा) को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ड्रग्स लाने-ले जाने और बेचने में इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्षा, कैश और मोबाइल फोन समेत कुल 3 करोड़ 5 लाख 260 रुपये का सामान ज़ब्त किया गया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अमोल कलजादे को पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ड्रग तस्करी के खिलाफ एक खास ऑपरेशन के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर की गई। 26 जुलाई, 2026 को रात करीब 10:30 बजे कल्याण फाटा में क्वीन्स केयर हॉस्पिटल के सामने



पब्लिक रोड पर जाल बिछाया गया था। जब संदिग्ध ऑटो रिक्षा की तलाशी ली गई, तो उसमें बेचने के लिए लाया गया 1.520 kg मेफेड्रोन (M.D.) मिला। जिसके बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में शील-डायघर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8(a), 22(a) और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 31 जुलाई, 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, और यह पता लगाने

के लिए जांच चल रही है कि उसे यह ड्रग किससे मिला और इसके पीछे और कौन सा रैकेट चल रहा है। यह शानदार ऑपरेशन क्राइम ब्रांच यूनिट-1 टीम ने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबेरे, जाईंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ज्ञानेश्वर चव्हाण, जाईंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) डॉ. पंजाबराव उमले, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) अमरसिंह जाधव और सीनियर अधिकारियों के गाइडेंस में सफलतापूर्वक किया।

'मैं अनाथ हू'

■ शिल्पा शिंदे ने
लॉक अप 2 में
खुदा जिंदगी से
जुड़ा कांदा राज
■ बोलीं- मेरे ही घर
से मुझे निकाल
दिया गया

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने लॉक अप 2 में अपनी लाइफ से जुड़ा एक भावुक किस्सा साझा किया। शो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और कंटेस्टेंट्स के हैरान कर देने वाले सीक्रैट्स सामने आ रहे हैं। हाल ही के एपिसोड में शिल्पा शिंदे ने अपना एक इमोशनल सीक्रैट रिवील करते हुए बताया कि जब उनके कंधे को सर्जरी हुई तो उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया गया। एक्ट्रेस का कहना था कि उनके पास फैमिली होकर भी फैमिली नहीं हैं। वह अनाथ हैं।

रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जाने वाला शो लॉक अप 2 इस समय काफी चर्चा में है। शो में सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे सीक्रैट्स बांट दिए गए, जिसके बाद टास्क के चलते शिल्पा शिंदे को अपना सीक्रैट साझा करना पड़ा। शिल्पा ने कहा- 'लोग फैमिली फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती और मेरे पास होकर भी मैं अनाथ हूँ।'

'मैं ये कोई सहानुभूति के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं शेल्टर हाउस में रहती हूँ, जब भी आती

हूँ। पहले करजत मेरा दूसरा घर था लेकिन अब वो मेरा पहला घर है, क्योंकि मैंने मुंबई छोड़ दिया है।'

मुझे मेरी ही घर से
निकाल दिया गया

शिल्पा ने आगे बताया कि '3 साल पहले मेरे कंधे की सर्जरी हुई थी, मेरा भाई अपनी पत्नी से प्रभावित हुआ, मेरी मां मेरे भाई से प्रभावित हुई और मेरी सर्जरी के पांचवें दिन मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया।'

शिल्पा बताती हैं कि 'हालात ऐसे बनाए गए और उन्हें पता था कि मैं बहुत स्वाभावी हूँ और मैं रात को 11 बजे वो घर छोड़कर चली गई। मुझे मेरी मां ने भी नहीं रोका। शिल्पा कहती हैं कि मैं अपने घर की डोरमैट बन गई थी। ये बताते हुए एक्ट्रेस को काफी भावुक देखा गया।'

डिप्टी सीएम ने ठाणे सिविल अस्पताल के काम का किया रिव्यू

ठाणे. ठाणे और आस-पास के पालघर जिलों के आम लोगों को अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं तुरंत देने के लिए, ठाणे में 900 बेड वाले सिविल अस्पताल, महिला और बच्चों के हॉस्पिटल और सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का काम बहुत जल्दी और 'फास्ट टैक' तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, यह निर्देश डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आज हुई एक मीटिंग में दिया। डिप्टी सीएम के कमिटी रूम में हुई इस मीटिंग में ठाणे सिविल अस्पताल की मौजूदा स्थिति और अब तक हुए काम की प्रोग्रेस का डिटेल में रिव्यू किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबटकर, मंत्री दादाजी भुसे, गुलाबराव पाटिल, उदय



सामंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, संजय राठोड़, प्रताप सरनाईक के साथ डिप्टी सीएम के एडिलनल चीफ सेक्रेटरी असीम गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन सोना, स्वास्थ्य सेक्रेटरी ई. रवींद्रन, जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, ठाणे अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार मौजूद थे। उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट

के हर फेज में काम की स्पीड बढ़ाते हुए यह पक्का करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल बिल्डिंग पूरी होने और बिजली कनेक्शन न होने की वजह से अस्पताल शुरू न हो पाने का मुद्दा सामने आने के बाद, उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल जैसी जरूरी सर्विस के लिए जरूरी सभी बिजली कनेक्शन का काम तय समय में पूरा किया जाए। इसके अलावा, डिप्टी

सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल बिल्डिंग की रेगुलर और हाई-क्वालिटी सफाई, अस्पताल में जरूरी लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट की तुरंत खरीद और सरकार द्वारा कुछ दिन पहले मंजूर किए गए 1078 नए पदों को भरने की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस बड़े 900 बेड वाले कॉम्प्लेक्स में, 500 बेड का नया अस्पताल, 200 बेड का इंटीग्रेटेड महिला और बच्चों का अस्पताल और 200 बेड का रेफरल सर्विस अस्पताल एक ही छत के नीचे काम करेंगे। कांडिवॉलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसी बहुत जरूरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुपरस्पेशलिटी डिपार्टमेंट मौजूद रहेंगे।

गैलरी का स्लैब गिरने
से 6 फंसे, 1 की मृत्यु

ठाणे. मुंबा में फैयाज अपार्टमेंट ग्राउंड + 4 मंजिल 38 साल पुराना निर्माण इमारत की दूसरी मंजिल की गैलरी का स्लैब पहली मंजिल पर गिर गया 1 लड़की की मृत्यु और 6 लोग फंसे गए। मौके पर फंसे लोगों को निकाला गया। जिसमें से 5 लोग सुरक्षित हैं और कुमारी अरुणा कादर शेख मजिल 13 साल रहने वाली - कमरा नंबर 102 को गंभीर चोटों के कारण इलाज के लिए ट्रेनपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, कलवा में भर्ती कराया गया, लेकिन मेडिकल ऑफिसर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। साथ ही, फैयाज अपार्टमेंट C2B कैटेगरी कुल 30 फ्लैट अभी 15 से 20 फ्लैट इस्तेमाल में है। बिल्डिंग को सुरक्षा कार्यों से पूरी तरह खाली करा लिया गया है और बिल्डिंग में रहने वाले लगभग 70 से 80 लोगों को स्कूल नंबर 78 और 123 में कुछ समय के लिए शिफ्ट किया।



उक्त घटना स्थल पर उप महापौर कृष्णा पाटिल, विपक्ष के नेता अशरफ शानू, पठान, उपायुक्त दीपक छिंजाड़, तापदा प्रबंधन अधिकारी वाई.एम. ठाडवा, सहायक आयुक्त विजय कवले, अग्निशमन विभाग स्टेशन अधिकारी गणेश खेतड़े, स्टेशन ऑफिसर सरोनबत के साथ टोरेट पावर कंपनी के स्टाफ मौजूद थे।

महिला से 22 लाख की ढगी

अंबरनाथ. एक 59 साल की गृहिणी से ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने का वादा करके 22 लाख रुपये की साइबर फ्रांड़ की गई। इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2025 में आरोपियों ने शिकायतकर्ता, उसके बेटे और बेटी से संपर्क किया और उन्हें एक लिंक के जरिए ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने पर आकर्षक रिटर्न का लालच दिया। आरोपियों के वादों पर विश्वास करके,



शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने संबंधित अकाउंट में कुल 22 लाख रुपये जमा कर लिए। हालांकि, जब उन्हें इन्वेस्ट की गई रकम या कोई भी प्रॉफिट वापस नहीं मिला, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है।